आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क

बनाम

एम/एस. होंगो इंडिया (पी) लिमिटेड एवं अन्य

सिविल अपील संख्या 1939, 2009

27 मार्च 2009

[मुख्य न्यायामूर्ति के.जी.बालाकृष्णन, न्यायाधिपति पी.सतशिवम

और जे.एम. पांचाल]

परिसीमा अधिनियम, 1963:

धारा 5-विलंब की क्षमा असंशोधित केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 35 एच (1) के तहत निर्देश आवेदन 180 दिवस की कालावधि में दायर करने में विलंब को क्षमा करने की शक्ति – अभिनिर्धारित किया गया: धारा 35 एच(1) के तहत निर्धारित समय पूर्ण और अविस्तारित है – धारा 5- इसलिए 180 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद विलंब क्षमा योग्य नहीं है - विधायी आशय का सम्मान करना न्यायालय का कर्तव्य है और उदार व्याख्या देकर, अधिनियम की धारा 5 को प्रयोग कर परीसीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है- केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944- धारा 35 एच(1) (पहले अधिनियम 49/2005) – क़ानून का निर्वचन

इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या उच्च न्यायालय के पास असंशोधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 एच(1) के तहत निर्देश आवेदन में परीसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत मुख्य क़ानून, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में निर्धारित अवधि से परे विलंब को माफ करने की शक्ति है।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1. उच्च न्यायालय के पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की असंशोधित धारा 35H(1) के तहत आयुक्त द्वारा दायर "निर्देश आवेदन"को 180 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक विलंब को क्षमा करने की कोई शक्ति नहीं है और निर्देश को परिसीमा के आदर पार सही खारिज कर दिया गया है। [पैरा 21] [1212-एफ-जी]

2. आयुक्त के पास अपील के मामले में, धारा 35, 60 दिनों का समय प्रदान करती है और इसके अतिरिक्त, यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया है, तो आयुक्त के पास 30 दिनों तक की देरी को माफ करने की शक्ति है। इसी तरह, धारा 35 बी, अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के लिए 90 दिनों का समय प्रदान करती है और उपधारा 5 अपीलीय न्यायाधिकरण को, यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया है, त कितने भी दिनों की देरी को माफ करने के लिए सक्षम बनाती है। इसी तरह, धारा 35 ईई जो केंद्र सरकार द्वारा पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय

प्रदान करती है और, इसका परंतुक पुनरीक्षण प्राधिकारी को पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर 90 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए देरी को माफ करने में सक्षम बनाता है, जबकि धारा 35 जी के तहत उच्च न्यायालय में अपील और असंशोधित अधिनियम की धारा 35 एच के तहत उच्च न्यायालय को निर्देश, के मामले में, अपील एवं निर्देश के उपचार का लाभ लेने के लिए कुल 180 दिनों की अवधि प्रदान की गई है। हालाँकि, 180 दिनों की अवधि के बाद देरी को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त बनाने वाला कोई और खंड नहीं है। निर्धारित अवधि के बाद पर्याप्त कारण दिखाकर देरी को माफ करने वाले किसी खंड के अभाव में, धारा 5 पूर्णत: निषेध है। इसलिए उच्च न्यायालय ने यह न्यायसंगत ठहराया की 180 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विलंब को माफ़ करने की कोई शक्ति नहीं थी। अन्यथा भी, आयुक्त और अपीलीय न्यायाधिकरण के पास अपील दायर करने के साथ-साथ केंद्र सरकार के पास पुनरीक्षण दायर करने के लिए, विधायिका ने क्रमश 60 एवं 90 दिवस की अवधि प्रदान की है। दूसरी ओर, उच्च न्यायालय में अपील और निर्देश दायर करने के लिए आयुक्त और दूसरे पक्ष को इसका लाभ उठाने के लिए 180 दिनों की बड़ी अवधि प्रदान की गई है। विधायिका ने उच्च न्यायालय में निर्देश दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय, अर्थात् 180 दिन प्रदान किया,

जो अपील और पुनरीक्षण के लिए निर्धारित अवधि से अधिक है। [पैरा 12,19] [1204-जी-एच; 1205-ए-सी; 1211-डी-एफ]

न्यायिक निर्णियों का उल्लेख किया गया है।

3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में प्रदान किए गए उपचार की प्रकृति ऐसी है कि विधायिका का आशय है कि यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता हो जो अकेले ही इसके द्वारा प्रदान किए गए कई मामलों को नियंत्रित करे। यदि, प्रासंगिक प्रावधानों की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि परीसीमा अधिनियम के प्रावधानों को आवश्यक रूप से बाहर रखा गया है, तो उसमें दिए गए लाभों को अधिनियम के प्रावधानों के पूरक के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता है। यहां तक कि ऐसे मामले में जहां विशेष कानून, एक स्पष्ट संदर्भ द्वारा परीसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को बाहर नहीं करता है, फिर भी न्यायालय के लिए यह जाँच करना उचित होगा कि क्या और किस हद तक, उन प्रावधानों की प्रकृति या विषय-वस्तु की प्रकृति और विशेष कानून की योजना उनके संचालन को बाहर करती है। इसलिए, परीसीमा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता का आकलन परीसीमा अधिनियम की शर्तों से नहीं, बल्कि उच्च न्यायालय में निर्देश आवेदन दाखिल करने से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों से किया जाना चाहिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की योजना इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि उच्च

न्यायालय में निर्देश दायर करने के लिए धारा 35 एच (1) के तहत निर्धारित समय सीमा, परीसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत न्यायालय द्वारा पूर्ण और अविभाज्य है। यह सुस्थापित विधि है कि विधायी आशय का सम्मान करना न्यायालय का कर्तव्य है और उदार व्याख्या देकर, अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को लागू करके परीसीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। [पैरा 20] [1210-ए-ई]

न्यायिक निर्णयों का उद्धरण

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1939,2009

केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 2003 की निर्देश आवेदन संख्या 14 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 07.02.2007 से।

के साथ

सिविल अपील सं. 1940/2009।

सिविल अपील सं. 1941/2009।

पराग पी. त्रिपाठी, एएसजी, के. राधाकृष्णन, अशोक के. श्रीवास्तव, अरुणा गुप्ता, अमेय नार्गलोकर, कुल भरत, अनिल कटियार, बी. कृष्णा प्रसाद- अपीलार्थीगण की ओर से।

मोनिश पांडे, एम. पी. देवनाथ, विनय गर्ग, दीपम गर्ग, ज्योति शर्मा, वी.के. सिंह, रूपल भाटिया, यशपाल दिंहगरा- प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. इन सभी अपीलों में, विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालय के पास केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (इसके बाद इसे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की असंशोधित धारा 35 एच (1) के तहत निर्धारित अवधि से अधिक समय में निर्देश आवेदन की प्रस्तुति में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू कर विलंब को माफ करने की शक्ति है। जब 2007 की एस.एल.पी. संख्या 14467 दिनांक 4/12/2008 सुनवाई के लिए आयी, तब दो न्यायाधीशों की पीठ ने आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, नोएडा बनाम पंजाब फाइबर्स लिमिटेड, नोएडा (2008) 3 एससीसी 73 के फैसले पर गौर करने के बाद अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि से परे विलंब को माफ करने के मामले में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में उक्त निर्णय पर संदेह व्यक्त किया। यह पता लगने के बाद कि असंशोधित अधिनियम की धारा 35 एच के तहत, निर्देश आवेदन के संबंध में, जहां सार्वजनिक महत्व के कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, उच्च न्यायालय ऐसे मामले में अपने सलाहकार क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है, उक्त खंडपीठ ने मामले की सुनवाई वृहत पीठ द्वारा करने का निर्देश दिया। इस प्रकार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णयों से उत्पन्न समान मुद्दे पर, उपर्युक्त सभी मामले इस

पीठ के समक्ष इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए रखे गए, अर्थात्, "क्या उच्च न्यायालय को असंशोधित अधिनियम की धारा 35H(1) के तहत निर्देश आवेदन में, सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत मुख्य क़ानून यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में निर्धारित अवधि से परे विलंब को माफ करने की शक्ति है?"

3. इन तीनों मामलों में, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में असंशोधित अधिनियम की धारा 35 एच (1) के तहत निर्देश आवेदन निर्धारित अवधि के बाद पेश किया। उच्च न्यायालय ने पहले के आदेशों पर भरोसा कर यह पाया कि उक्त प्रावधान के तहत निर्देश आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने की उनके पास कोई शक्ति नहीं है, निर्देश आवेदन को सीमा से वर्जित मानकर खारिज कर दिया।

4. अधिनियम का अध्याय vi-ए अपील से संबंधित है। धारा 35 के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा पारित किसी भी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे निर्णय या आदेश की सूचना मिलने की दिनांक से साठ दिनों के भीतर केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (अपील) में अपील कर सकता है। उप-धारा (1) का परंतुक आयुक्त (अपील) को सक्षम बनाता है, यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को साठ दिनों की पूर्वोक्त

अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था, तो तीस दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर प्रस्तुत करने की अनुमति दें।

5. धारा 35 बी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के बारे में बताती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त या आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी निर्णयों/आदेशों से व्यथित कोई भी व्यक्ति, अपीलीय न्यायाधिकरण में जिस आदेश के विरुद्ध अपील करने की मांग की गई है, उसकी संबंधित अधिकारी या दूसरे पक्ष को सूचना मिलने की दिनांक से तीन महीने के भीतर अपील कर सकता है। उपधारा (5) अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्धारित अवधि से अधिक विलंब को भी माफ करने में सक्षम बनाती है यदि उस अवधि के भीतर इसे प्रस्तुत न करने का पर्याप्त कारण हो।

6. धारा 35 ईई केंद्र सरकार द्वारा पुनरीक्षण प्रदान करती है। उपधारा (2) के अनुसार, उपधारा (1) के तहत आवेदन सूचना मिलने की तारीख से तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए। हालाँकि, उप-धारा (2) का परंतुक, पुनरीक्षण प्राधिकारी को पर्याप्त कारण दर्शाने पर नब्बे दिनों की अवधि के लिए विलंब को माफ करने में सक्षम बनाता है।

7. असंशोधित धारा 35 जी उच्च न्यायालय में अपील के बारे में बताती है। उपधारा 2(ए) पीड़ित व्यक्ति को केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या अन्य पक्ष द्वारा अपील किए गए आदेश की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर करने में सक्षम बनाती है। अपील

दायर करने में 180 दिनों की निर्धारित अवधि से अधिक देरी को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है।

8. असंशोधित धारा 35 एच उच्च न्यायालय में निर्देश आवेदन के बारे में बताती है। उप-धारा (1) के अनुसार, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त या अन्य पक्ष उस तारीख से 180 दिनों की अवधि के भीतर, जिस दिन उसे धारा 35 सी के तहत आदेश का नोटिस दिया जाता है, न्यायाधिकरण को किसी भी विधि के प्रश्न की जो न्यायाधिकरण के ऐसे आदेश से उत्पन्न होता है, उच्च न्यायालय में संदर्भित करने का निर्देश देता है। यहां फिर से उप-धारा (1) के अनुसार, निर्देश आवेदन 180 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में किया जाना है और उच्च न्यायालय में आवेदन दायर करने की परीसीमा अवधि को उक्त अवधि से आगे बढ़ाने और विलंब क्षमा करने का कोई प्रावधान नहीं है।

9. उच्च न्यायालय मे पेश तीन अपीलों में अंतर्गत केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 49/2005 (28.12.2005 से लागू)संशोधन से पूर्व की धारा 35 एच (1) के तहत उच्च न्यायालय में किए गए "संदर्भ आवेदन"से चिंतित हैं, जिसमे अधिनियम की धारा 35 एच सहित विभिन्न प्रावधानों को हटा दिया गया। हालाँकि, दिए गए संदर्भ को देखते हुए हमारे सामने संदर्भित प्रश्न पर विचार करना उचित है। इन सभी मामलों में, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 180 दिनों की निर्धारित अवधि से बाद

संदर्भ आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, अधिनियम की योजना के संदर्भ में और सीमा अधिनियम की धारा 5 को लागू करने के लिए विशिष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति में, अन्य प्रावधानों यानी धारा 35, 35 बी और 35 ईई पर ध्यान दिया, जो अन्य प्राधिकारियों को, यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया तो देरी को माफ करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तदनुसार, परिसीमा के आधार पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा दायर संदर्भ आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा।

10. अब विचार करें कि क्या परिसीमा अधिनियम की धारा 5 असंशोधित अधिनियम की धारा 35 एच के तहत उच्च न्यायालय में दायर संदर्भ आवेदन के संबंध में लागू है।

11. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री पराग पी. त्रिपाठी ने तर्क दिया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय के पास सभी अंतर्निहित और पूर्ण शक्तियाँ हैं, वह अधिनियम के तहत निर्धारित अवधि के बाद भी विलम्ब पर विचार करने में सक्षम है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के बदले में विशेष रूप से धारा 35 एच में देरी को माफ करने के लिए अधिनियम में विशिष्ट निषेध के अभाव में, परिसीमा अधिनियम की धारा 5 लागू है और उच्च न्यायालय को विलम्ब क्षमा करने मे अपनी

शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। उन्होंने शुरू में तर्क दिया कि चूंकि धारा 35 एच सार्वजनिक महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करती है, इसलिए देरी, यदि कोई हो, को माफ किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए रुख का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम अपने आप में एक स्व-निहित अधिनियम और एक संहिता है और उच्च न्यायालय को विलंब को माफ करने की शक्ति प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाले विशिष्ट प्रावधान के अभाव के कारण, उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि से परे दायर उत्पाद शुल्क विभाग के संदर्भ आवेदन पर विचार करने से इनकार करना उचित है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनियम की योजना और इस तथ्यों के मद्दनजरमें कि आयुक्त के साथ-साथ अन्य पक्ष को उच्च न्यायालय का संदर्भ देने के लिए पर्याप्त अवधि, यानी 180 दिन प्रदान की गई है, विधायी मंशा है सम्मान किया जाना है।

12. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसके पास स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति सहित सभी शक्तियां होंगी। हालाँकि हमने अपने आदेश के पहले भाग में धारा 35 एच

का उल्लेख किया है, लेकिन उप-धारा (1) को निकालना बेहतर है जो प्रासंगिक है और इन अपीलों से संबंधित हैं:

> "35 एच। उच्च न्यायालय में आवेदन-(1) आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क या अन्य पार्टी, एक सौ के भीतर हो सकती है और उस तारीख के अस्सी दिन, जिस दिन उसे सेवा दी जाएगी धारा 35 सी के तहत पहले पारित एक आदेश की सूचना 1 जुलाई, 2003 (इससे संबंधित कोई आदेश नहीं है।) अन्य बातें, किसी भी प्रश्न के निर्धारण के लिए उत्पाद शुल्क की दर या के मूल्य से संबंध मूल्यांकन के प्रयोजनों के लिए माल), में आवेदन द्वारा निर्धारित प्रपत्र, संलग्न, जहां आवेदन है दूसरे पक्ष द्वारा दो सौ रुपये शुल्क लेकर बनाया गया। अपीलीय न्यायाधिकरण को निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करें कानून संबंधी कोई भी प्रश्न उठने पर उच्च न्यायालय का संदर्भ लें ट्रिब्यूनल का ऐसा आदेश।"

यदि उच्च न्यायालय में निर्देश आवेदन उक्त निर्धारित अवधि से परे किया जाता है तो 180 दिनों की अवधि प्रदान करने के अलावा, विलम्ब को माफ करने के लिए कोई अन्य प्रावधान नहीं है। हमने पहले ही बताया है कि आयुक्त को अपील के मामले में, धारा 35 60 दिनों का समय प्रदान

करती है और इसके अतिरिक्त, यदि पर्याप्त कारण दिखाया गया है, तो आयुक्त के पास 30 दिनों तक की देरी को माफ करने की शक्ति है। इसी तरह, धारा 35 बी अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील दायर करने के लिए 90 दिनों का समय प्रदान करती है और उप-धारा (5) अपीलीय न्यायाधिकरण को पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर दिनों की संख्या की परवाह किए बिना, विलम्ब को माफ करने में सक्षम बनाती है। इसी तरह, धारा 35 ईई जो केंद्र सरकार द्वारा पुनरीक्षण दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय प्रदान करती है और, इसका परन्तुक, पुनरीक्षण प्राधिकारी को पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर 90 दिनों की अतिरिक्त अवधि के लिए देरी को माफ करने में सक्षम बनाता है, जबकि उच्च न्यायलय में अपील और धारा 35 एच के तहत उच्च न्यायालय को निर्देश के मामले में अपील और संदर्भ के उपचार का लाभ उठाने के लिए कुल 180 दिनों की अवधि प्रदान की गई है। हालाँकि, 180 दिनों की अवधि के बाद विलम्ब को माफ करने के लिए उच्च न्यायालय को सशक्त बनाने वाला कोई और प्रावधान नहीं है

13. परिसीमा अधिनियम की धारा 5 और धारा 29(2) पर भरोसा जताया गया जो इस प्रकार है:

> "5. कुछ मामलों में निर्धारित अवधि का विस्तार। सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के किसी भी प्रावधान

के तहत आवेदन के अलावा कोई भी अपील या कोई आवेदन, निर्धारित अवधि के बाद स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलकर्ता या आवेदक अदालत को संतुष्ट करता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त कारण थे।"

"29. बचत, (1) इस अधिनियम में कुछ भी भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (1872 का 9) की धारा 25 को प्रभावित नहीं करेगा।

(2) जहां कोई विशेष या स्थानीय कानून किसी मुकदमे के लिए निर्धारित करता है। अपील या आवेदन अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि से भिन्न सीमा की अवधि है, धारा 3 के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि ऐसी अवधि अनुसूची द्वारा निर्धारित अवधि थी और किसी भी मुकदमे, अपील के लिए निर्धारित सीमा की अवधि निर्धारित करने के उद्देश्य से या किसी विशेष या स्थानीय कानून द्वारा लागू होने पर, धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधान केवल उसी हद तक लागू होंगे, जहां तक और जिस हद तक, उन्हें ऐसे विशेष या स्थानीय कानून द्वारा स्पष्ट रूप से बाहर नहीं रखा गया है।"

14. इस पृष्ठभूमि में, हमने दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए विवादों की जांच की। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भारत संघ बनाम मेसर्स पॉपुलर कंस्ट्रक्शन कंपनी, (2001) 8 एससीसी 470 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताते हुए तर्क दिया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम में परीसीमा अधिनियम के विशिष्ट बहिष्करण की अनुपस्थिति में, उच्च न्यायालय में निर्देश आवेदन के मामले में भी परिसीमा अधिनियम की धारा 29 (2) के स्थान पर, इसकी धारा 5 लागू होती है। उक्त निर्णय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत उत्पन्न हुआ। इस मामले में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के प्रावधान मध्यस्थता और सुलह अभिनियम की धारा 34 के तहत एक अधिनिर्णय को चुनौती देने वाले आवेदन पर लागू होते हैं। उस मामले में, दिनांक 29.3.1999 को बॉम्बे उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता-भारत संघ द्वारा अधिनिर्णय दायर किया गया था। अपीलकर्ता ने 19.4.1999 को मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 16 सपठित धारा 30 के तहत अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए एक आवेदन दायर किया। इसके बाद, "मध्यस्थता अधिनियम, 1996" के स्थान पर "मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996" शब्द लिखकर आवेदन में संशोधन किया गया। आवेदन को विद्वान एकल न्यायाधीश ने 26.10.1999 को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह आवेदन 1996 अधिनियम

की धारा 34 के तहत परिसीमा द्वारा वर्जित था। डिवीजन बेंच ने अपील खारिज कर विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों को बरकरार रखा। यद्यपि अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपने दावे के समर्थन में उक्त निर्णय पर भरोसा जताया, लेकिन उसका अवलोकन करने पर, हम उससे सहमत होने में असमर्थ हैं। पैरा 12 में, इस न्यायालय ने माना कि जहां तक 1996 अधिनियम की धारा 34 की भाषा का संबंध है, उप-धारा (3) के परंतुक में प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द "लेकिन उसके बाद नहीं"हैं और यह वाक्यांश परिसीमा अधिनियम की धारा 29(2) के अर्थ के अंतर्गत विशिष्ट बहिष्करण के बराबर होगा, और इसलिए, अधिनियम की धारा 5 के प्रयोग प्रतिबन्ध लगता है। संसद को आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि न्यायालय परन्तुक के तहत निर्धारित अवधि से परे अधिनिर्णय को रद्द करने के आवेदन पर विचार कर सकता है, "लेकिन उसके बाद नहीं"के वाक्यांश को पूरी तरह से निरर्थक बना देगा। निर्वचन का कोई भी सिद्धांत ऐसे परिणाम को उचित नहीं ठहराएगा। अंततः, इस न्यायालय ने भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि अधिनिर्णय को रद्द करने के लिए दायर आवेदन परीसीमा से वर्जित है।

14) विद्वान एएसजी द्वारा अगले निर्णय शारदा देवी बनाम बिहार राज्य, (2002) 3 एससीसी 705 के मामले पर भरोसा जताया गया। यह

एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में लेटर्स पेटेंट बेंच के समक्ष अपील से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 54 पर विचार करते समय, इस न्यायालय ने निम्नानुसार कहा:

> "9. एक लेटर्स पेटेंट वह चार्टर है जिसके तहत उच्च न्यायालय स्थापित है. उच्च न्यायालय को दी गई शक्तियाँ लेटर्स पेटेंट के तहत संवैधानिक के समान हैं उच्च न्यायालय की शक्तियाँ. इस प्रकार जब कोई लेटर्स पेटेंट अनुदान देता है किसी निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय को अपील करने की शक्ति एकल न्यायाधीश को अपील पर विचार करने का अधिकार होगा जब तक वैधानिक अधिनियम संबंधित न हो, बाहर नहीं रखा जाएगा लेटर्स पेटेंट के तहत अपील को शामिल नहीं किया गया है।

10. इस प्रकार जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या उक्त अधिनियम की धारा 54 लेटर्स पेटेंट के तहत अपील का वर्जन करती है। उक्त अधिनियम की धारा 54 इस प्रकार है:

> ""54. न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में अपील - के अधीन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान, मूल डिक्री की अपीलों पर लागू, और किसी भी अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी होते हुए भी फिलहाल लागू होने पर,

अपील केवल किसी में ही की जाएगी इस अधिनियम के तहत कार्यवाही से लेकर उच्च न्यायालय तक पुरस्कार, या न्यायालय के पुरस्कार के किसी भी भाग से और ऐसी अपील पर पारित उच्च न्यायालय के किसी भी डिक्री सेजैसा कि ऊपर कहा गया है, अपील उच्चतम न्यायालय में की जाएगी की धारा 110 में निहित प्रावधानों के अधीनसिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, और उसके आदेश 45 में।"

यह तर्क दिया गया कि उक्त अधिनियम की धारा 54 में एक गैर-अप्रत्याशित खंड है जिसमें "अपील केवल की जाएगी" शब्द शामिल हैं। यह पता लगाने के बाद कि लेटर्स पेटेंट एक अधिनियम नहीं है, यह उच्च न्यायालय का चार्टर है, इस न्यायालय ने पाया कि इस प्रकृति का एक गैर-अप्रचलित खंड उच्च न्यायालय के चार्टर को कवर नहीं कर सकता है। धारा 54 को दर्शाते हुए यह तर्क दिया गया कि उक्त अधिनियम उच्च न्यायालय में केवल एक वैधानिक अपील और फिर आगे इस न्यायालय में अपील का प्रावधान करता है। अर्थात, यह प्रस्तुत किया गया कि धारा 54 को पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि एक लेटर्स पेटेंट अपील, धारा 54 के तहत अपील में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित फैसले के खिलाफ नहीं होगी। दूसरे पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक लेटर्स पेटेंट अपील की जा सकेगी। उक्त तर्क को स्वीकार

करते हुए, इस न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि उक्त अधिनियम की धारा 26 में प्रावधान है कि प्रत्येक अधिनिर्णय एक डिक्री होगा और प्रत्येक अधिनिर्णय के आधार का विवरण एक निर्णय होगा। लेटर्स पेटेंट के आधार पर उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ "अपील" एक डिवीजन बेंच में की जाएगी। उक्त अधिनियम की धारा 54 लेटर्स पेटेंट के तहत अपील का वर्जन नहीं करती है। यह स्पष्ट किया गया कि धारा 54 में गैर-अप्रत्याशित खंड के तुरंत बाद आने वाला शब्द "केवल" अपील के न्यायलय को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, यह प्रावधान करता है कि अपील उच्च न्यायालय में होगी, किसी अन्य न्यायलय में नहीं और "अपील" शब्द इसे उच्च न्यायालय में केवल एक अपील तक सीमित नहीं करता है। यह समझाया गया कि "अपील" शब्द एक लेटर्स पेटेंट अपील को भी अपने दायरे में लेता है। हालाँकि विद्वान एएसजी ने उपर्युक्त तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा जताया, हमारा विचार है कि उक्त निर्णय उच्च न्यायालय की लेटर्स पेटेंट शक्ति से संबंधित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लेटर्स पेटेंट के तहत उच्च न्यायालय को दी गई शक्तियाँ उच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्तियों के समान हैं। ऐसी परिस्थितियों में, जब एक लेटर्स पेटेंट उच्च न्यायालय को एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ अपील की शक्ति प्रदान करता है, तो अपील पर विचार करने का अधिकार तब तक वर्जित नहीं किया जाएगा जब तक कि

संबंधित वैधानिक अधिनियम लेटर्स पेटेंट के तहत अपील को वर्जित नहीं करता है। चूँकि लेटर्स पेटेंट उच्च न्यायालय को सक्षम बनाता है कि एकल न्यायाधीश का निर्णय डिवीजन बेंच के पास जायेगा और इस तथ्य के बावजूद कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 54, लेटर्स पेटेंट के तहत अपील को वर्जित नहीं करती है, उक्त निर्णय यह मानते हुए सही है कि धारा 54 के तहत लेटर्स पेटेंट अपील पर कोई रोक नहीं है। हालाँकि लेटर्स पेटेंट क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में कोई विवाद नहीं है, हमारा विचार है कि उक्त सादृश्य मौजूदा मामलों पर लागू नहीं होता है।

16. अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जिस अन्य निर्णय पर भरोसा जताया गया। विद्वान एएसजी एम.वी. एलिजवेथ और अन्य बनाम हर्वन इनवेस्टमेन्ट और ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड हनोऐकर हाउस स्वातोन्टापेथ वास्को डी गामा गोवा, 1993 पूरक 2 एससीसी 433 में निम्नलिखित टिप्पणियों पर बहुत अधिक भरोसा जताया:

> "66 भारत में उच्च न्यायालय अभिलेख के श्रेष्ठ न्यायालय हैं। उनके पास अंतर्निहित और पूर्ण शक्तियां हैं और अभिलेख न्यायालय होने के कारण उनके पास अपनी अधिकारिता को निर्धारित करने की शक्तियों को शामिल करते हुए असीमित क्षेत्राधिकार है। जब तक कि अभिव्यक्त रूप से या विवक्षित

रूप से वर्जित नहीं किया जाता है, और इस न्यायालय के अपीलीय या विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालयों के पास असीमित क्षेत्राधिकार है, जिसमें उनको अपनी शक्तियां को निर्धारित करने का क्षेत्राधिकार भी शामिल है..."

यहां भी, उपरोक्त प्रस्तावना पर कोई विवाद नहीं है। भारत में उच्च न्यायालयों के पास अंतर्निहित और पूर्ण शक्तियाँ हैं और रिकॉर्ड न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालयों के पास अपनी शक्तियों को निर्धारित करने के क्षेत्राधिकार सहित असीमित क्षेत्राधिकार है। हालाँकि, उक्त सिद्धांत को अधिनियम में विशिष्ट प्रावधानों के साथ और अधिनियम की योजना के प्रकाश में तय किया जाना है, विशेष रूप से, असंशोधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 35, 35 बी, 35 ईई, 35 जी और 35 एच के मामले में, यह मानना संभव नहीं होगा कि उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के बावजूद, उच्च न्यायालय 180 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद भी निर्देश याचिका पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है।

17) जिस अन्य निर्णय पर भरोसा किया गया।[1] यह मामला नियत दिन (10.05.1971) को केरल राज्य के सभी निजी वनों को केरल निजी वन (निहित और समनुदेशन) अधिनियम, 1971 के तहत केरल राज्य में

[1]एम.एम. थॉमस बनाम केरल राज्य और अन्य (2000) 1 एससीसी 666

निहित करने से उत्पन्न हुआ था। यह सच है कि पैरा 14 में यह माना गया था कि अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय के पास, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 215 में परिकल्पित है, अभिलेख को सही करने के लिए अंतर्निहित शक्तियां होनी चाहिए। अभिलेख न्यायालय ऐसी सभी शक्तियों को समाहित करता है जिनके कृत्यों और कार्यवाहियों को एक सतत स्मारक और स्मृति के रूप में नामांकित किया जाना है। अभिलेख न्यायालय निस्संदेह एक श्रेष्ठ न्यायालय है जो अपने अधिकार क्षेत्र का दायरा निर्धारित करने में स्वयं सक्षम है। अभिलेख न्यायालय के रूप में उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह अपने सभी अभिलेखों को सही ढंग से और विधि के अनुसार रखे। इसलिए, उच्च न्यायालय के पास न केवल शक्ति है, बल्कि उसके द्वारा पारित किसी भी आदेश के संबंध में किसी भी स्पष्ट त्रुटि को सुधारने का कर्तव्य भी है। यह उच्च न्यायालय की पूर्ण शक्ति है। उपर्युक्त निर्णय के पैरा 17 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था:

> "17. यदि उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के अभिलेख में जब वह स्पष्ट त्रुटियों को देखता है, सही करने की ऐसी शक्ति से वंचित कर दिया जाता है, तो इसका परिणाम यह होता है कि उच्च न्यायालय की श्रेष्ठ स्थिति कम हो जाएगी। इसलिए, यह सोचना उचित है कि उच्च न्यायालय की पूर्ण

शक्तियों में अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटियों से संबंधित पुनर्विलोकन की शक्ति भी शामिल होगी।"

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिलेख में स्पष्ट त्रुटियों को सुधारने के लिए उच्च न्यायालय के पास सभी शक्तियाँ हैं। उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, अधिनियम की योजना के प्रकाश में, हमारा विचार है कि उक्त निर्णय भी अपीलकर्ता द्वारा अपनाए गए रुख के लिए सहायक नहीं है।

18. हमारे आदेश के पहले भाग में, हमने अधिनियम के अध्याय VIA का उल्लेख किया है जो विभिन्न प्राधिकारियों को अपील और पुनरीक्षण के प्रावधान प्रदान करता है। हालाँकि संसद ने विशेष रूप से आयुक्त को अपील के मामले में 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि प्रदान की है, लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील के मामले में पर्याप्त कारण होने पर दिनों की संख्या के बारे में यह चुप है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पुनरीक्षण के मामले में 90 दिनों की अतिरिक्त अवधि भी प्रदान की गई है। हालाँकि, धारा 35 जी के तहत उच्च न्यायालय में अपील और धारा 35 एच के तहत उच्च न्यायालय में निर्देश याचिका के मामले में, संसद ने केवल 180 दिन प्रदान किए हैं और अधिनियम में अपील दायर करने और उच्च न्यायालय को निर्देश याचिका देने के लिए कोई अतिरिक्त अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है। इस संबंध में, पंजाब फाइबर्स लिमिटेड, नोएडा (सुप्रा) में इस न्यायालय के एक हालिया फैसले का उल्लेख करना उपयोगी

होगा। सीमा शुल्क आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नोएडा इस मामले में अपीलकर्ता हैं। इसी प्रश्न पर विचार करते समय, अर्थात्, क्या उच्च न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 35 एच(1) के तहत निर्देश याचिका की प्रस्तुति में देरी को माफ करने की शक्ति है? दो-न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त प्रावधान और अन्य संबंधित प्रावधानों पर ध्यान दिया। सिंह एंटरप्राइजेज बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, जमशेदपुर और अन्य , (2008) 3 एससीसी 70 के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि "उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि संदर्भ आवेदन दाखिल करने में देरी को माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी।

19) जैसा कि पहले बताया गया है, धारा 35, 35 बी, 35 ईई, 35 जी और 35 एच में प्रयोग की गई भाषा इस स्थिति को स्पष्ट करती है कि उच्च न्यायालय में अपील और निर्देश केवल निर्णय या आदेश की संसूचना की दिनांक से 180 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अन्य प्रावधानों में प्रयोग की गई भाषा स्थिति को स्पष्ट करती है कि विधायिका का आशय अपीलीय प्राधिकारी को 60 दिनों की समाप्ति के बाद केवल 30 दिनों तक के विलम्ब को माफ करके अपील पर विचार करने की शक्ति प्रदान करती है, जो कि अपील को प्रस्तुत करने के लिए प्रारंभिक परिसीमा अवधि है। विहित अवधि के बाद पर्याप्त कारण दिखाकर विलम्ब को माफ करने वाले किसी खंड के अभाव में, परिसीमा अधिनियम की धारा

5 का पूर्ण वर्जन है। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह मानना उचित था कि 180 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद विलम्ब को माफ करने की कोई शक्ति नहीं थी। अन्यथा भी, आयुक्त और अपीलीय न्यायाधिकरण के के समक्ष अपील दायर करने के लिए साथ ही केंद्र सरकार के समक्ष पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करने क लिए, विधायिका ने क्रमशः 60 दिन और 90 दिन प्रदान किए हैं, दूसरी ओर, उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने और निर्देश के लिए आयुक्त और दूसरे पक्ष को में सक्षम बनाने के लिए उच्च न्यायालय को 180 दिनों की अवधि प्रदान की गई है। हमारा विचार है कि विधायिका ने उच्च न्यायालय में निर्देश याचिका दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय, अर्थात् 180 दिन प्रदान किया, जो अपील और पुनरीक्षण के लिए निर्धारित अवधि से अधिक है।

20) हालाँकि, परिसीमा अधिनियम की धारा 29 के आधार पर एक तर्क उठाया गया था, यह मानते हुए भी कि धारा 29(2) आकर्षित होगी, हमें यह निर्धारित करना है कि क्या इस धारा के प्रावधानों को उच्च न्यायालय को किये गए पुनर्विलोकन के मामले में स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। हमारे सामने यह तर्क दिया गया था कि "अभिव्यक्त रूप से वर्जित" शब्दों का अर्थ यह होगा कि विशेष या स्थानीय विधि में परिपरिसीमा अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों के उन प्रावधानो के लिए, जिसके संचालन को वर्जित किया जाना है, एक स्पष्ट निर्देश होना चाहिए।

इस संबंध में, हमें यहां विशेष विधि की योजना को देखना होगा, इस मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम है। इसमें प्रदान किए गए उपचार की प्रकृति ऐसी है कि विधायिका का आशय था कि यह अपने आप में एक पूर्ण संहिता हो जो अकेले ही उसके द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न मामलों को शासित करे। यदि, सुसंगत प्रावधानों की समीक्षा करने पर, यह स्पष्ट है कि परिपरिसीमा अधिनियम के प्रावधानों को आवश्यक रूप से बाहर रखा गया है, तो उसमें दिए गए लाभों को इस अधिनियम के प्रावधानों के पूरक के रूप में नहीं कहा जा सकता है। हमारे विचार में, ऐसे मामले में भी जहां विशेष विधि एक स्पष्ट निर्देश द्वारा परिपरिसीमा अधिनियम की धारा 4 से 24 के प्रावधानों को वर्जित नहीं किया जाता है, फिर भी यह जांच करने के लिए न्यायालय के पास शक्ति है कि क्या और किस हद तक, उन प्रावधानों की प्रकृति या विषय-वस्तु की प्रकृति और विशेष विधि की योजना उनके संचालन को वर्जित करती है। दूसरे शब्दों में, परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता, परिसीमा अधिनियम की शर्तों से नहीं बल्कि उच्च न्यायालय में निर्देश याचिका दाखिल करने से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के प्रावधानों से तय की जानी चाहिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की योजना इस निष्कर्ष का समर्थन करती है कि उच्च न्यायालय को संदर्भ देने के लिए धारा 35 एच(1) के तहत निर्धारित समय परिसीमा परिसीमा अधिनियम की धारा

5 के तहत अदालत द्वारा पूर्ण और अविस्तारित है। यह अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि विधायी इरादे का सम्मान करना अदालत का कर्तव्य है और उदार व्याख्या देकर, अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों को लागू करके परिसीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता है।

21) उपरोक्त चर्चा के प्रकाश में, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय के पास असंशोधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 एच(1) के तहत आयुक्त द्वारा दायर "निर्देश याचिका" को 180 दिनों की निर्धारित अवधि करने में पश्चात संस्थित करने के विलम्ब को माफ करने की कोई शक्ति नहीं है और परिपरिसीमा के आधार पर निर्देश याचिका को खारिज करना उचित है।

22) उपरोक्त निष्कर्ष के मद्देनजर, हम उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हैं। अतः तदनुसार सभी अपीलें खारिज की जाती हैं। खर्चो के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं।

अपील खारिज की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास'की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सीमा चौहान(आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।